सुभाष चंद

बनाम

राजस्थान राज्य

अक्टूबर 16, 2001

[डॉ. ए. एस. आनंद, सी. जे., आर. सी. लाहोटी और अशोक भान, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 313-लागू होने का दायरा और परिधि- अभिनिर्धारितः क्या अभियुक्त को किसी भी साक्ष्य में आई आपत्तिजनक परिस्थिति को समझाने का अवसर देना है-अभियुक्त इस तरह के अवसर का लाभ उठा सकता है या नहीं भी।

आपराधिक मुकदमाः

'आखिरी बार एक साथ देखा गया'-पुष्टि करने के लिए साक्ष्य- अभिनिर्धारितः ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित और अभियुक्त को अपराध के समय और तिथि के निकट समय पर एक साथ देखा गया हो।

वीर्य और खून -अभियुक्त के कपड़ों पर उपस्थिति का प्रमाणिक मूल्य- अभिनिर्धारितः अपने आप में अभियुक्त को विचाराधीन अपराध के साथ जोड़ने हेतु सबूत का एक दोषपूर्ण टुकड़ा नहीं-दंड संहिता, 1860, धारा 376।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-इस आधार पर दोषसिद्धि-अभिनिर्धारितः अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का दावा ऐसा है कि अभियुक्त की निर्दोषता की संभावना को खारिज किया जा सके-'सच हो सकता है' और 'सच होना चाहिए' के बीच यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी है-ऐसी दूरी को कानूनी, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा तय किया जाना चाहिए।

आपराधिक अपराध-जांच-जांच अधिकारी की भूमिका को समझाया और दोहराया गया।

शब्द और वाक्यांशः " अलीबी "-का अर्थ है।

अपीलार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 376 (2) (च) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एस, लगभग 5 साल की एक छोटी लड़की को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। मृतक के कपड़ों पर समूह-बी का मानव रक्त पाया गया। अपीलार्थी-अभियुक्त को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और उसके कहने पर, एक सूखे कुएँ में एक अंडरवियर और 'बनियान' पाए गए थे। अंडरवियर पर मानव वीर्य

और समूह-बी के मानव रक्त का पता चला। अभियुक्त के खिलाफ निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य थेः

(i) आखिरी बार एक साथ देखा गया;

(ii) अभियुक्त का असामान्य आचरण।

(iii) अंडरवियर और 'बनियां' (जो पाया गया था) की बरामदगी

वीर्य और रक्त समूह 'बी' से सना हुआ जो मृतक का रक्त समूह था);

(iv) अन्यत्र उपस्थिति की झूठी दलील; और

(v) अभियुक्त अपराध दिनांक से फरार है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. आखिरी बार एक साथ देखा गया 'आखिरी बार एक साथ देखे गए' का साक्ष्य बनाने के लिए, साक्ष्य को निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देनी चाहिए कि पीड़ित और अभियुक्त को अपराध के समय और तारीख के करीब एक बिंदु पर एक साथ देखा गया था। पीडब्लू-7 के साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। [171 – बी]

2. अभियुक्त का असामान्य आचरण कोई भी व्यक्ति, भले ही वह निर्दोष हो और किसी भी तरह से किसी जघन्य अपराध से जुड़ा न हो जो हाल ही में हुआ था और जो शहर में चर्चा का विषय था, अगर पुलिस उसे बुलाती है और संदिग्ध के रूप में पूछताछ करती है, तो वह डर जाएगा

और उसके फंसने की संभावना से आशंकित होगा| ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रामीण, कानून से अनभिज्ञ होकर, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछता है, जिसे वह महसूस करता है कि वह खुद जो करता है उससे बेहतर चीजों को जानता है, कि इस तरह के अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को कारावास की अवधि कितनी भुगतनी होगी, पूछताछ के लिए आवेग घबराहट की भावना या केवल जिज्ञासा का परिणाम हो सकता है; ऐसी जांच आवश्यक रूप से एक आपराधिक दिमाग के काम करने का संकेत नहीं है। [172 – एफ-जी]

3. खून और वीर्य से सना अंडरवियर की बरामदगी अंडरवियर पर वीर्य के दाग की मौजूदगी, यह मानते हुए कि अंडरवियर आरोपी का था, हालांकि इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, यह अपने आप में आरोपी को संबंधित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। इसलिए अंडरवियर पर 'बी' समूह के खून के धब्बे की खोज को आरोपी के खिलाफ अपराध से जोड़ने वाले सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अंडरवियर आरोपी का था और आगे भी इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया गया है कि अंडरवियर उस व्यक्ति के खून से सना हुआ हो जिसका वह था, या यदि आरोपी ने इसे पहना था। [173 - एच; 174-ए-बी]

शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1981) एससी 765 पर निर्भरता रखी।

4. अन्यत्र उपस्थिति की झूठी दलील

(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य आरोपी को व्यक्तिगत रूप से किसी भी साक्ष्य में उपस्थित आपत्तिजनक परिस्थिति को समझाने का अवसर प्रदान करना है। अभियुक्त अपना स्पष्टीकरण देने के अवसर का लाभ उठा भी सकता है और नहीं भी। [174 – एफ]

(ख) ऐलिबी का शाब्दिक अर्थ 'अन्यत्र' है। कानून में इस शब्द का उपयोग आपराधिक अभियोजन में उस बचाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जहां आरोपी पक्ष यह साबित करने के लिए कि वह उसके खिलाफ आरोपित अपराध नहीं कर सकता था, सबूत पेश करता है कि वह उस समय एक अलग जगह पर था। ली गई दलील का अर्थ यह होना चाहिए कि उस समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए जब और जहां उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह उपस्थित नहीं हो सकता था। अन्यत्र स्थान पर उपस्थिति के कारण अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति की भौतिक असंभवना को अन्यत्र प्रकट करने की दलील दी गई है। [174 - एच; 175-ए]

लॉ लेक्सिकनः पी. रामंता अय्यर, द्वितीय संस्करण , पी. 87, संदर्भित।

(ग) एक आरोपी द्वारा अपने मालिक द्वारा दिए गए दावे से इनकार करना कि आरोपी अपराध की तारीख पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की छुट्टी पर था, किसी भी तर्क के आधार पर, अन्यत्र उपस्थिति की दलील देने के बराबर नहीं है। [1750 – बी]

5. अभियुक्त अपराध दिनांक से फरार है। अभियुक्त को कई बार जाँच के दौरान पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। इस प्रकार, वह हमेशा पुलिस के लिए उपलब्ध रहता था। घटना के दो दिन बाद आरोपी सिनेमा हॉल में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि अपराध की तारीख के तुरंत बाद आरोपी अपने निवास या अपने रोजगार के स्थान से गायब पाया गया था और खोजे जाने के बावजूद वह उस स्थान या स्थानों पर उपलब्ध नहीं था जहां उसे सामान्य रूप से जाना चाहिए था। रहा। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी फरार था। [175 – जी-एच]

6.1 विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया उनमें से किसी भी साक्ष्य को आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।यद्यपि अपराध

वीभत्स है और मानव विवेक को विद्रोह करता है, लेकिन किसी आरोपी को केवल कानूनी सबूतों के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है और यदि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक श्रृंखला इस तरह से बनाई गई है कि आरोपी के अपराध को छोड़कर किसी अन्य उचित परिकल्पना की संभावना को खारिज कर दिया जाए। [176 – बी]

धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1994] 2 एस. सी. सी 220, शरद बिरधीचंद_सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1984] 4 एस. सी. सी. 116 और शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 765, पर निर्भर

6.2 सच हो सकता है और सच होना चाहिए, इसके बीच यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी होती है जिसे किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा तय किया जाना चाहिए। [176 – सी]

7. अनजान अपराध किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध किए जाने का तथ्य तो ज्ञात है लेकिन न तो अभियुक्त की पहचान का खुलासा किया गया है और न ही उन गवाहों का कोई संकेत उपलब्ध है जो उपयोगी और प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। ऐसे अपराध एक जांच अधिकारी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हैं। एक सतर्क जांच अधिकारी, जो काम की तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ है, अपराधी तक पहुंचने वाले

रास्ते का पता लगाते हुए सबूतों के धागे इकट्ठा करने की स्थिति में है। आपराधिक न्याय प्रशासन जो लक्ष्य हासिल करता है, वह केवल अपराधी को पकड़ने से हासिल नहीं होता। आरोप को अदालत में साबित करना होगा।

अदालत में दिए गए जांच अधिकारी के साक्ष्य में चरण दर चरण यह बताने वाली लय होनी चाहिए कि कैसे जांच आगे बढ़ी जिससे अपराधी का पता लगाया गया और उसके खिलाफ सबूत एकत्र किए गए। यह इस बात की संभावना को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी निर्दोष को उठाया जाएगा और उसे अपराधी करार दिया जाएगा और फिर अपराध की गंभीरता मानवीय सहानुभूति जगाएगी, मन को संदिग्ध या संदेहास्पद परिस्थितियों से दूर ले जाएगी और उन्हें 'संदेह से परे' साक्ष्य मूल्य के रूप में माना जाएगा। [176 - एफ-एच; 177-ए]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 230-231/ 1999

राजस्थान उच्च न्यायालय डी. बी. सी. आर. एल. ए. नं. 453 और 1993 का 455 निर्णय और आदेश दिनांक 18.12.95 से के दिनांक 16.1.98 से।

सुशील के. जैन, ए. मिश्रा, सुश्री अंजलि दोशी और सुश्री रुचि कोहली अपीलार्थी की ओर से।

सुश्री संध्या गोस्वामी और जावेद एम. राव प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, जे. द्वारा सुनाया गया।

अभियुक्त-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 376(2)(एफ) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत 10,000 रुपये का भुगतान न करने पर 3 साल के लिए अतिरिक्त आजीवन कठोर कारावास भुगतना होगा। जबकि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 366 के तहत मौत की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया, अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की। आपराधिक संदर्भ और आपराधिक अपील की सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ का गठन करने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों की राय अलग-अलग थी। एक विद्वान न्यायाधीश की राय में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिस पर अभियोजन का मामला निर्भर करता है, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप पर दोषी साबित होने के लिए पर्याप्त नहीं था। अन्य विद्वान न्यायाधीश की राय में, अभियोजन पक्ष के सबूत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया था, हालांकि,

मामला उन 'दुर्लभतम मामलों' में से एक नहीं था, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए थी।

इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए, विद्वान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के तहत मामले को तीसरे न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए सौंपा। तीसरे विद्वान न्यायाधीश ने सबूतों की स्वतंत्र सराहना करते हुए, आरोपी की दोषसिद्धि को दोनों आरोपों पर बरकरार रखते हुए अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज किए हैं और इस प्रकार निष्कर्ष में खंडपीठ का गठन करने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों में से एक के साथ सहमति व्यक्त की। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन साबित पाए गए दोनों आरोपों पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा को शामिल करते हुए सजा में संशोधन के अधीन दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

लगभग 5 वर्ष की छोटी बच्ची कुमारी एस को आखिरी बार 18 मार्च, 1991 को शाम लगभग 4 बजे देखा गया था और उसके बाद वह घर नहीं लौटी। 19 मार्च 1991 को सुबह लगभग 7 बजे किशोरी लाल, पीडब्लू4 ने एस के अभागे पिता बीडी (पीडब्लू2) को सूचित किया कि कोटपूतली गांव

के बाहरी इलाके में मोहल्ला बसेरा के पास एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। बीडी वहां पहुंचे तो देखा कि शव किसी और का नहीं बल्कि उनकी ही बेटी एस का था। उसके मुंह और निजी अंग से खून बह रहा था। उसके गले में फंदा भी लगा मिला। दिनांक 19.3.1991 को प्रातः 7.25 बजे बी.डी. द्वारा पुलिस थाना कोटपूतली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आई.पी.सी. की धारा 302 और 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया । जांच शुरू हो गई| शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो उसी दिन सुबह 9.30 बजे तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया।यह पाया गया कि पीड़िता के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। चिकित्सकीय राय के अनुसार एस की मृत्यु का संभावित कारण योनि में आघात और पोस्ट-फॉर्निक्स के टूटने के साथ-साथ गर्दन के चारों ओर बंधन के कारण दम घुटने के कारण हुआ उत्पन्न सदमा था। पीड़ित के शरीर पर पाई गई सभी चोटें पोस्टमार्टम के समय से लगभग 24 घंटे पहले की हो सकती हैं। योनि की चोटें, जमा हुआ खून और पोस्ट-फोर्निक्स की चोटें पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने का संकेत दे रही थीं। शव से कपड़े उतारकर कब्जे में ले लिए। रक्त और वीर्य के धब्बों के साइटो-रासायनिक विश्लेषण के लिए योनि स्वाब की स्लाइड तैयार की गईं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने मृतक के कपड़ों पर ग्रुप-बी रक्त की उपस्थिति की पुष्टि की।

अभियुक्त को संदेह के आधार पर 3.4.1991 को गिरफ्तार किया गया था। 4.4.1991 को उसकी चिकित्सीय जांच की गई। उसके निजी अंग या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं थी|उसके कपड़ों पर खून या वीर्य का कोई दाग नहीं था। वह 21 साल का वयस्क पुरुष था और संभोग क्रिया करने में सक्षम था।

5.4.1991 को लगभग 12.30 बजे उसने एक सूचना प्रदर्श पी/23 दी और सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस को एक सूखे कुएं तक ले जाया गया, जहां से 18.3.1991 के अखबार में लिपटा एक अंडरवियर और बनियान बरामद हुआ। बरामद कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। रिपोर्ट एग्जीबिट के अनुसार. अंडरवियर पर पी/27 मानव वीर्य पाया गया। रिपोर्ट प्रदर्श पी-30 के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंडरवियर पर समूह 'बी' का मानव रक्त पाया गया।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरोपी का चालान कर दिया गया और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

अभियोजन पक्ष ने कुल 21 गवाहों को प्रकाशित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करना यहां आवश्यक नहीं है। यह देखना पर्याप्त है कि अभियुक्त को आरोपित अपराधों से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के टुकड़े जो साबित पाए गए हैं

और अभियुक्त के खिलाफ अभियोगात्मक श्रृंखला बनाने के रूप में माने गए हैं, वे इस प्रकार हैं:-

(i) आखिरी बार एक साथ देखा गया था;

(ii) अभियुक्त का असामान्य आचरण;

(iii) अंडरवियर और बनियान की बरामदगी (जो वीर्य और रक्त समूह 'बी' से सना हुआ पाया गया, जो मृतक का रक्त-समूह भी है);

(iv) अन्यत्र उपस्थिति की झूठी दलील; और

(v) अभियुक्त अपराध दिनांक से फरार है।

हम परिस्थितिजन्य सबूतों के प्रत्येक टुकड़े की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रत्येक परिस्थितिजन्य साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से साबित हुआ है और क्या सामूहिक रूप से यह आपत्तिजनक परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला बनाता है जो अभियुक्त को उचित संदेह की छाया से परे बांध देगा।

धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, [1994] 2 एससीसी 220, (जिसमें हममें से एक, डॉ. एएस आनंद, जे., ने बेंच के लिए बात की थी) इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें

न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि स्थापित सभी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। उन परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न छूटे। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ, न कि केवल अदालत का आक्रोश, दोषसिद्धि का आधार बन सकता है और अपराध जितना अधिक गंभीर होगा, सबूतों की जाँच करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण की जगह ना ले सके न हो।"

धनंजय चटर्जी के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1984] 4 एससीसी 116 निर्णय पर भरोसा किया गया था। बाद के मामले में, यह भी माना गया कि अभियुक्त द्वारा ली गई झूठी व्याख्या या झूठी दलील को तीन आवश्यक शर्तों की संतुष्टि के अधीन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात् (i) श्रृंखला में विभिन्न कडी

अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूत संतोषजनक ढंग से साबित किए गए हैं, (ii) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और (iii) परिस्थिति समय और स्थिति के करीब है।

(i) आखिरी बार एक साथ देखा गया:

आखिरी बार एक साथ देखे जाने के बिंदु पर एक बाल गवाह शालू, पीडब्लू 7, की एकमात्र गवाही है, जिसकी उम्र 23.3.1992 को लगभग 4 साल थी, जो अदालत में उसकी परीक्षा की तारीख थी।प्रारंभिक परीक्षण के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि गवाह 'कुछ प्रश्नों का उत्तर' दे सकता है। उसने बताया कि, फुक्ला-एक अन्य युवा लड़की, उसकी चचेरी बहन और मृतक एस के साथ, वह गोमा की दुकान से गुब्बारा खरीदने गई थी। लौटते समय अभियुक्त ने एस को बताया कि उसके पैर कीचड़ से सने हैं और वह उसके पैर धोएगा और इतना कहकर वह एस को अपने घर के अंदर ले गया, दो लड़कियों शालू पीडब्लू 7 सहित को पीछे छोड़ दिया, जो एस को छोड़कर अपने घर लौट आईं।

यह वह गवाही है जिस पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी 'आखिरी बार एक साथ देखे जाने' के साक्ष्य के रूप में भरोसा किया है। गवाह बहुत कम उम्र का एक बाल गवाह है और घटना की तारीख के लगभग एक साल बाद अदालत में प्रकाशित हुआ है| हमने इस गवाह के

बयान को बहुत ध्यान से पढ़ा है| उसके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि वह अदालत में जो बता रही है वह घटना की तारीख और समय से या जिस तारीख को एस का शव मिला था से एक दिन पहले की कहानी है| आखिरी बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य बनाने के लिए, साक्ष्य को निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देनी चाहिए कि पीड़ित और अभियुक्त को अपराध के समय और तारीख के करीब एक बिंदु पर एक साथ देखा गया था। शालू, पी.ड.-7 के साक्ष्य से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

गोमा, जिसकी दुकान पर तीनों लड़कियाँ गुब्बारे खरीदने गई थीं, उसको परीक्षित नहीं करवाया गया है।

घटना के गवाह के रूप में शालू की खोज में कुछ रहस्यमय है। एस की मृत्यु हो गई है| तीसरी लड़की जो एस और शालू के साथ थी, उससे न तो अदालत में और न ही जांच के दौरान प्रकाशित किया गया है। साहू का बयान जांच के दौरान 25.3.1991 को दर्ज किया गया, यानी घटना की तारीख के लगभग छह दिन बाद। जांच अधिकारी हरीश चंद शर्मा से खास तौर पर पूछा गया कि जांच के दौरान इस गवाह का नाम उनकी जानकारी में कैसे आया? उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि गवाहों के बयान में यह बात जरूर सामने आई होगी कि शालू एस के साथ थी।आगे उनसे उस गवाह का नाम बताने के लिए कहा गया जिसके बयान में शालू का

संदर्भ उपलब्ध था, लेकिन जांच अधिकारी ने कुछ नहीं कहा और वह उस गवाह का नाम नहीं बता सके जिससे उन्हें शालू के बारे में कोई सुराग मिला था। इस प्रकार जांच अधिकारी को कैसे और किस तरीके से शालू, पीडब्लू 7 के बारे में पता चला ताकि जांच के दौरान उसका बयान दर्ज किया जा सके, यह रहस्य में घिरा हुआ है।

तथ्य यह है कि 4 साल की शालू, पीडब्लू 7 की गवाही, भले ही बिल्कुल स्पष्ट ली जाए, तो भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई आपत्तिजनक निष्कर्ष निकाला जाए और उसे अपराध से जोड़ा जाए।

(ii) अभियुक्त का असामान्य आचरण,

कालू राम, पी.डब्ल्यु.-5 ने कहा कि एस का शव मिलने की तारीख के दो या तीन दिन बाद, वह और संतोष, पी.डब्ल्यु.9 एक सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने गए थे जहाँ अभियुक्त एक द्वारपाल के रूप में कार्यरत था। वहां अभियुक्त ने उनसे पूछा था कि किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अपराधी को क्या सजा दी जा सकती है।

गवाह ने अभियुक्त को बताया कि सजा 20 या 40 साल की कैद या आजीवन कारावास भी हो सकती है। इसके बाद गवाह सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले गए। जिरह के दौरान, कालू राम ने कहा कि अभियुक्त उसका पड़ोसी था, जिसे वह पहले से जानता था|एक प्रासंगिक प्रश्न पर

साक्षी ने बताया कि ऐसा प्रश्न करते समय अभियुक्त के चेहरे के हाव-भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात् वह सामान्य बना रहा।

संतोष, पीडब्लू 9, ने कालू राम के संस्करण का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया। इस सवाल पर जाए बिना कि क्या कालू राम, पीडब्लू5 के बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि संतोष पीडब्लू9 ने इसका समर्थन नहीं किया है, आइए हम इस तरह की गवाही के आंतरिक मूल्य का आकलन अपराध साबित करने वाले साक्ष्य के रूप में करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत में एस की मौत एक अंधी हत्या थी और पुलिस को संभावित अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने तलाशी अभियान की शुरू किया और उस प्रक्रिया में कई संदिग्ध पात्रों को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। हरीश चंद शर्मा, पीडब्लू 21 ने कहा कि 19 से 25 मार्च 1991 के बीच अभियुक्त सुभाष को पूछताछ के लिए कई बार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। उन्हें याद नहीं है और इसलिए वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि आरोपी सुभाष को कितनी बार पूछताछ या जांच के लिए बुलाया गया था| केस डायरी देखने पर उन्होंने बताया कि 21.3.1991 को अभियुक्त को एक ही दिन में दो बार जरूर बुलाया गया था, हालांकि उससे क्या पूछताछ की गई, इसका कोई जिक्र नहीं है।हालांकि, अभियुक्त को हिरासत

में नहीं लिया गया और वापस भेज दिया गया| कोई भी व्यक्ति, भले ही वह निर्दोष हो और किसी भी तरह से किसी जघन्य अपराध से जुड़ा न हो जो हाल ही में हुआ था और जो शहर में चर्चा का विषय था, अगर पुलिस उसे बुलाती है और संदिग्ध के रूप में पूछताछ करती है, तो वह डर जाएगा और उसके फंसने की संभावना से आशंकित होगा|ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रामीण, कानून से अनभिज्ञ होकर, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछता है, जिसे वह महसूस करता है कि वह खुद जो करता है उससे बेहतर चीजों को जानता है, कि इस तरह के अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को कारावास की अवधि कितनी भुगतनी होगी, पूछताछ के लिए आवेग घबराहट की भावना या केवल जिज्ञासा का परिणाम हो सकता है; ऐसी जांच आवश्यक रूप से एक आपराधिक दिमाग के काम करने का संकेत नहीं है।

(iii) खून और वीर्य से सने अंडरवियर की बरामदगी

अजीब बात है कि अंडरवियर और बनियान को हालांकि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किए गए एक बयान पर स्पष्ट रूप से इंगित करने पर खोजा और जब्त किया गया था, लेकिन अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं किया गया है। पता नहीं इन कपड़ों का क्या हुआ? यह पता लगाने की दिशा में कोई जांच नहीं की गई है और कोई सबूत एकत्रित और अदालत में पेश यह दिखाने के लिए पेश नहीं किया गया है कि अंडरवियर और बनियान

आरोपी के थे। जहां तक बनियान की बात है तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, इसलिए इसकी खोज और जब्ती अर्थहीन और अप्रासंगिक है। जहां तक अंडरवियर का सवाल है, जांच एक अन्य कमज़ोरी से भी ग्रस्त है।अभियुक्त का रक्त नमूना एकत्रित नहीं किया गया था और इसलिए उसे समूहीकृत नहीं किया गया।यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि आरोपी का ब्लड ग्रुप क्या था और इसलिए अंडरवियर पर खून आरोपी के ही होने की संभावना नहीं हो सकती है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है।दागों की संख्या और फैलाव का दायरा भी ज्ञात नहीं है।

अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन ने शंकरलाल गयारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1981) एससी 765 पर निर्भरता रखी है। इसमें धारा 376 और 302 आई.पी.सी. के तहत आरोप को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर प्रमाणित करने की मांग की गई थी। जिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया गया उनमें से एक यह था कि आरोपी की पैंट पर 'बी' समूह का मानव रक्त का धब्बा पाया गया था, जो रक्त समूह मृतक का भी था। एक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया वह यह था कि आरोपी के अंडर-पैंट पर वीर्य का एक दाग पाया गया था। पैरा 28 के अनुसार, इस न्यायालय ने माना कि 0.5 सेमी मापने वाले 'बी' समूह के रक्त-धब्बे की अपीलकर्ता की पैंट पर उपस्थिति और उसके अंडर-पैंट पर वीर्य का सूखा दाग, ऐसी

परिस्थितियाँ थीं जो यह स्थापित करने के लिए बहुत कमजोर थीं कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया या उसकी हत्या की। 'बी' समूह रक्त का असामान्य समूह नहीं है और इस संभावना को बाहर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अभियुक्त का रक्त उसी समूह का था। अपीलकर्ता के अंडर-पैंट पर वीर्य के सूखे दाग के संबंध में, अदालत ने कहा कि आरोपी 30 साल का एक वयस्क व्यक्ति था और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका कि यह दाग उसके द्वारा पीड़ित लड़की पर किए गए यौन उत्पीड़न के दौरान लगा था।

मौजूदा मामले में घटना के वक्त आरोपी की उम्र करीब 21 साल थी। उसकी गिरफ़्तारी पर उनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया और पाया गया कि वह एक जननक्षम और सक्षम व्यक्ति थे।अंडरवियर पर वीर्य के दाग की मौजूदगी, यह मानते हुए कि अंडरवियर आरोपी का था, हालांकि इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, यह अपने आप में आरोपी को संबंधित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। इसलिए अंडरवियर पर 'बी' समूह के खून के धब्बे की खोज को आरोपी के खिलाफ अपराध से जोड़ने वाले सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अंडरवियर आरोपी का था और आगे भी इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया गया है कि अंडरवियर उस व्यक्ति के खून से सना हुआ हो जिसका वह था, या यदि आरोपी ने इसे पहना था।

(iv) अन्यत्र उपस्थिति की झूठी दलील

उच्च न्यायालय यह मानने में पूरी तरह गलत हो गया है कि आरोपी ने अन्यत्र उपस्थिति की दलील दी थी और वह झूठी पाई गई। अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान के दौरान यह नहीं कहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के दौरान कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि घटना के समय वह ऐसी जगह पर था जहां से वह अपराध की तारीख और उसके होने के समय तक नहीं पहुंच सकता था। हालाँकि पीड़ित का शव गाँव के बाहरी इलाके में पाया गया था, लेकिन वहाँ उस स्थान और संभावित समय को पक्का करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिस पर एस पर बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी| विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अन्यत्र उपस्थिति की दलील के रूप में माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी स्थानीय टॉकीज 'हीरा मोती' में एक आकस्मिक (नियमित नहीं) द्वारपाल के रूप में कार्यरत था। सिनेमा हॉल के मालिक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 18 और 19 मार्च को आरोपी ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली थी और उन दिनों वह ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। यह सबूत आरोपी के सामने धारा 313 के तहत उसके बयान के दौरान रखा गया था और जवाब में उसने 'गलत है' (सही नहीं) कहा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य आरोपी को व्यक्तिगत रूप से किसी भी साक्ष्य में उपस्थित

आपत्तिजनक परिस्थिति को समझाने का अवसर प्रदान करना है। अभियुक्त अपना स्पष्टीकरण देने के अवसर का लाभ उठा भी सकता है और नहीं भी। अभियुक्त ने मौके का फायदा नहीं उठाया और केवल यह कहकर चुप रह गया कि सिनेमा मालिक का बयान सही नहीं था।

ऐलिबी का शाब्दिक अर्थ 'अन्यत्र' है।कानून में इस शब्द का उपयोग आपराधिक अभियोजन में उस बचाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जहां आरोपी पक्ष यह साबित करने के लिए कि वह उसके खिलाफ आरोपित अपराध नहीं कर सकता था, सबूत पेश करता है कि वह उस समय एक अलग जगह पर था। ली गई दलील का अर्थ यह होना चाहिए कि उस समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए जब और जहां उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह उपस्थित नहीं हो सकता था। अन्यत्र स्थान पर उपस्थिति के कारण अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति की भौतिक असंभवना को अन्यत्र प्रकट करने की दलील दी गई है। (लॉ लेक्सिकन, पी. रामनाथ अय्यर, द्वितीय संस्करण, पृ.87 देखें)। एक आरोपी द्वारा अपने मालिक द्वारा दिए गए दावे से इनकार करना कि आरोपी अपराध की तारीख पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की छुट्टी पर था, किसी भी तर्क के आधार पर, अन्यत्र उपस्थिति की दलील देने के बराबर नहीं है।

हमारी स्पष्ट राय है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने कोई अन्यत्र उपस्थिति की दलील नहीं ली है और इसलिए इसे गलत ठहराने और फिर उसके प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का सवाल ही नहीं उठता।

(v) अभियुक्त का फरार होना

क्या अभियुक्त फरार था? घटना की तारीख के बाद आरोपी के फरार होने को एक तथ्य मानकर और फिर तथाकथित फरारी को आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में मानकर आरोपी के साथ गंभीर अन्याय किया गया है।हरीश चंद शर्मा के अनुसार, आरोपी को 3.4.1991 को बहरोड़ में गिरफ्तार किया गया था, जो लगभग कोटपूतली गांव से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है, जहां घटना हुई थी. हालाँकि आरोप है कि आरोपी को बहरोड़ में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी ज्ञापन बहरोड़ में तैयार नहीं किया गया था; इसे कोटपूतली गांव में तैयार किया गया था. गिरफ्तारी ज्ञापन में आरोपी की गिरफ्तारी बहरोड़ में होने का उल्लेख नहीं है। यदि आरोपी को बहरोड़ में गिरफ्तार किया गया तो कोई कारण नहीं है कि गिरफ्तारी ज्ञापन ग्राम बहरोड़ में तैयार न किया गया हो। कम से कम इस तथ्य का उल्लेख गिरफ्तारी ज्ञापन में किया जाना चाहिए था, भले ही वह ज्ञापन कोटपूतली गांव में तैयार किया गया हो। दूसरे, हरीश चंद शर्मा स्वयं कहते हैं कि 19.3.1991 से 25.3.1991 के बीच अभियुक्त को कई बार पुलिस स्टेशन में

बुलाया गया था और 21.3.1991 को ही उसे एक दिन में दो बार बुलाया गया था।इस प्रकार, वह हमेशा पुलिस के लिए उपलब्ध रहता था। कालू राम, पीडब्ल्यु5, अपने एक दोस्त संतोष, पीडब्ल्यु 9 के साथ घटना की तारीख के दो दिन बाद सिनेमा टॉकीज हीरा-मोती में एक फिल्म देखने गए थे और वहां आरोपी अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि अपराध की तारीख के तुरंत बाद आरोपी अपने निवास या अपने रोजगार के स्थान से गायब पाया गया था और खोजे जाने के बावजूद वह उस स्थान या स्थानों पर उपलब्ध नहीं था जहां उसे सामान्य रूप से जाना चाहिए था। रहा। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी फरार था।

निष्कर्ष

इस प्रकार, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया उनमें से किसी भी साक्ष्य को आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। यद्यपि अपराध वीभत्स है और मानव विवेक को विद्रोह करता है, लेकिन किसी आरोपी को केवल कानूनी सबूतों के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है और यदि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक श्रृंखला इस तरह से बनाई गई है कि आरोपी के अपराध को छोड़कर किसी अन्य उचित परिकल्पना की संभावना को खारिज कर दिया जाए। शंकरलाल ग्यारसीलाल

दीक्षित के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी - "जब क्रूर अपराधों का सामना करना पड़ता है, तो मानव स्वभाव मजबूत संदेह से कहानियाँ गढ़ने के लिए बहुत इच्छुक होता है"। इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि सच हो सकता है और सच होना चाहिए, इसके बीच यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी होती है जिसे किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा तय किया जाना चाहिए।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में पांच टुकड़ों की उपलब्धता की धारणा पर आगे बढ़े हैं, जिनमें से जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमने पाया है कि चार कथित परिस्थितियां आपत्तिजनक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के टुकड़े नहीं हैं। हमारे पास केवल परिस्थिति क्रमांक 3 बची है अर्थात, वीर्य और मानव रक्त समूह 'बी' से सने अंडरवियर और बनियान की बरामदगी, जो अकेले, यहां ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, आरोपित अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलकर्ता की सजा का आधार नहीं बन सकता है।

मामले से अलग होने से पहले हम मामले के एक पहलू को छूते हुए अपना एक अवलोकन रिकॉर्ड में रखना चाहेंगे। अनजान अपराध किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध किए जाने का तथ्य तो ज्ञात है लेकिन न तो अभियुक्त की पहचान का खुलासा किया गया है और न ही उन गवाहों का कोई संकेत

उपलब्ध है जो उपयोगी और प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। ऐसे अपराध एक जांच अधिकारी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हैं। एक सतर्क जांच अधिकारी, जो काम की तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ है, अपराधी तक पहुंचने वाले रास्ते का पता लगाते हुए सबूतों के धागे इकट्ठा करने की स्थिति में है। आपराधिक न्याय प्रशासन जो लक्ष्य हासिल करता है, वह केवल अपराधी को पकड़ने से हासिल नहीं होता। आरोप को अदालत में साबित करना होगा। अदालत में दिए गए जांच अधिकारी के साक्ष्य में चरण दर चरण यह बताने वाली लय होनी चाहिए कि कैसे जांच आगे बढ़ी जिससे अपराधी का पता लगाया गया और उसके खिलाफ सबूत एकत्रित किए गए। यह इस बात की संभावना को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी निर्दोष को उठाया जाएगा और उसे अपराधी करार दिया जाएगा और फिर अपराध की गंभीरता मानवीय सहानुभूति जगाएगी, मन को संदिग्ध या संदेहास्पद परिस्थितियों से दूर ले जाएगी और उन्हें 'संदेह से परे' साक्ष्य मूल्य के रूप में माना जाएगा।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376(2)(एफ) के तहत अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया है।उस पर लगाए गए आरोपों से उसे बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

वी. एस. एस. अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जया चतुर्वेदी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।